(c) what is the manner in which the said Board is likely to be constituted; and

(d) by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) to (d) It is proposed to set up a National Marine Fisheries Development Board as a Registered Society during the Eighth Five Year Plan period for the overall development of marine fishery in the country. The objectives of the Board are given in the statement.

Statement

The National Marine Fishery Development Board will be set up to :—

(1) assist/carry out a developmental role in the marine fishery sector and to take up commercial deep sea fishing projects involving fishing, processing & marketing. Such projects should be pioneering ones and should act a model to fishery entrepreneurs.

(2) coordinate and strengthen the efforts of public, cooperative and private organisations (small, medium and large) engaged in the exploitation of marine fishery sources.

(3) assist in financing of fishery projects and channolize government assistance.

(4) help in building a domestic fish marketing system (including promotion) and coordinate with export promotion agencies.

(5) help in creation of infrastructural facilities in marine fishery sector and operate the same.

(6) project training requirements in deep sea fishing sector and help in organising the training.

(7) provide consultancy in deep sea fishing and fish processing.

(8) conduct/get conducted need-based commercial surveys of fishery resources in Indian EEZ—Test fishing.

(9) collaborate with foreign companies/agencies for development of marine fishery sector.

भूतपूर्व अनुसूचित जनजाति आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार

1037. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**
श्री विशम्भर नाथ पांडे :
श्री एन० ई० बलराम :
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में "पूर्व जनजाति आयुक्त को निर्वस्त्र कर घुमाया गया" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) दोषी व्यक्तियों को बिना किसी विलम्ब से दंडित करने के लिए क्या सरकार ने मध्य प्रदेश की, राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य संक्षेप में, निम्न प्रकार हैं:

डा० बी० डी० शर्मा ने जगदलपुर में प्राइवेट क्षेत्र में स्टील प्लांट लगाने के लिए जमीन न देने हेतु ग्रामवासियों को उकसाने की कोशिश की। दूसरी ओर बस्तर जिले के औद्योगिक विकास और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बस्तर विकास संघर्ष समिति ने स्टीलप्लांट लगाने का स्वागत करते हुए डा० शर्मा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की अनुचित माना। 15-10-1992 को

स्टील प्लांट लगाने का समर्थन व विरोध करने वाली पार्टियों ने रैलियों का आयोजन किया।

28-10-1992 को डा० शर्मा बेरंगपाल गांव जा रहे थे। बस्तर विकास संघर्ष समिति के कुछ समर्थकों ने डा० शर्मा को रोका और उसे बस्तर के विकास में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया। तत्पश्चात वे डा० शर्मा को जबरदस्ती जगदलपुर लाए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और डा० शर्मा को पुलिस थाने लेआए। डा० शर्मा की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 342, 294, 323 के अंतर्गत मामला सं० 75/92 दर्ज किया गया। डा० शर्मा को, उनको लगी चोटों के लिए, डाक्टरी जांच करवाने के लिए कहा गया किन्तु डा० शर्मा ने डाक्टरी जांच करवाने के लिए लिखित रूप में इंकार कर दिया। तत्पश्चात्, कोई डाक्टरी जांच नहीं की गई। इस मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

29-10-92 को अन्य गांवों का दौरा करने के लिए डा० शर्मा के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से, उनके लिए गार्ड की व्यवस्था की गई।

Deployment of B.S.F. Personnel

1038. SHRI V. RAJESHWAR RAO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what is the total strength of the Border Security Force and the total amount of expenditure annually incurred on B.S.F. during each of the last three years;

(b) what is the number of Border Security Force personnel put on duties not meant for B.S.F. during the same period and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) A statement is enclose. (*See* below).

(b) B.S.F. personnel are performing duties which they are required to perform under the BSF Act and Rules.

STATEMENT

Total Strength and annual expenditure incurred on B.S.F. for the last 3 years

(Rs. in thousands)

Sl. No.	Year	Strength	Actual expenditure
1.	1989-90	1,54,971	507,81,86
2.	1990-91	1,72,696	651,05,86
3.	1991-92	1,72,894	719,24,29

Laying of Mines Across Bangladesh Border

1039. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to lay mines on the border of India and Bangladesh in areas of West Bengal, Assam and Mizoram;

(b) whether such a proposal fraught with grave consequences has been thought of under the pressure of motivated propaganda regarding infiltration;

(c) whether the news of such intention may not foul up our relation with neighbours and may not show us poor light to the international community; and

(d) whether laying of mines particularly in peace time exposing a simple introducer to death will be in consonance with humanitarian approach we boost of is not with provisions of International law ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF